



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2233]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2012/कार्तिक 15, 1934

No. 2233]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2012/KARTIKA 15, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2012

का.आ. 2685(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यहां नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थाओं को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कर मुक्त, प्रतिभूत, उन्मोचनीय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करने के लिए अधिकृत करती है जिसकी कुल राशि उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित है:

(क) पात्रता.- निम्नलिखित बांड सब्सक्राइब करने के लिए पात्र होंगे:-

- (i) फुटकर व्यक्तिगत निवेशक (आर आई आई);
- (ii) अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यू आई बी);
- (iii) कारपोरेट;
- (iv) अधिक निवल मूल्य वाले व्यष्टि (एच एन आई);

(ख) बांड की अवधि.- (i) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
(आईआईएफसीएल) के मामले में बांड की अवधि दस, पंद्रह या बीस वर्ष होगी;

(ii) अन्य मामलों में, बांड की अवधि दस या पंद्रह वर्ष होगी;

- (ग) स्थाई खाता संख्या.- सब्सक्राइबर्स के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे जारीकर्ता को अपना स्थाई खाता संख्या प्रस्तुत करें;
- (घ) ब्याज दर.- (i) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर के आधार पर कूपन दर पर सीलिंग होगी;
- (ii) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर पब्लिक इश्यू के मामले में एक्सचेंज या कम्पनी रजिस्ट्रार (आर ओ सी) के पास अंतिम प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से ठीक पूर्व शुक्रवार को समाप्त दो सप्ताह तथा निजी नियोजन के मामले में इश्यू खोलने की तारीख के लिए विद्यमान दैनिक आधार (कार्य दिवस) पर भारतीय नियत आय धन बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएडीए) द्वारा सूचित समतुल्य परिपक्वता के लिए सरकारी प्रतिभूति के बेस यील्ड का औसत होगी;
- (iii) ए ए रेटेड जारीकर्ताओं के लिए सीलिंग कूपन दर फुटकर व्यक्तिगत निवेशकों (आर आई आई) के मामले में 50 आधार प्वाइंट घटाकर संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर होगी; और अन्य निवेशक सिगमेंट, जैसे कि अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यू आई बी), कारपोरेट एवं अधिक निवल मूल्य के व्यष्टियों (एच एन आई) के लिए सीलिंग कूपन दर 100 आधार प्वाइंट घटाकर संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर होगी;
- (iv) यदि जारीकर्ता की रेटिंग ए ए से अधिक होगी, तो ए ए रेटेड संस्थाओं के लिए सीलिंग दर की तुलना में सीलिंग दर में 15 आधार प्वाइंट की कटौती की जाएगी [जैसा कि खंड (iii) में दिया गया है] ;
- (v) ये सीलिंग दरें ब्याज के वार्षिक भुगतान के लिए लागू होंगी तथा यदि ब्याज भुगतान की अनुसूची बदलकर अर्धवार्षिक की जाती है, तो ब्याज दर में 15 आधार प्वाइंट की कटौती की जाएगी;
- (vi) फुटकर निवेशकों पर लागू ब्याज की उंची दर बांड हस्तांतरित किए जाने के मामले में उपलब्ध नहीं होगी, ऐसे मामले को छोड़कर जहां मूल निवेशक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बांड कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाता है;
- (ड.) निर्गम खर्च एवं दलाली.- (i) निजी नियोजन के मामले में, कुल निर्गम खर्च इश्यू के आकार के 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा पब्लिक इश्यू के मामले में यह इश्यू के आकार के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
- (ii) निर्गम खर्च में निर्गम से संबंधित सभी खर्च जैसे कि दलाली, विज्ञापन, मुद्रण, पंजीकरण आदि शामिल होंगे;

(iii) विभिन्न श्रेणियों के मामले में दलाली निम्नलिखित सीलिंग तक सीमित होगी;

- (i) क्यू आई बी - 0.05 प्रतिशत
- (ii) कार्पोरेट - 0.1 प्रतिशत
- (iii) एच एन आई - 0.15 प्रतिशत
- (iv) आर आई आई - 0.75 प्रतिशत

(च) पब्लिक इश्यू- (i) प्रत्येक संस्था द्वारा जारी किए गए बांड की सकल राशि का कम से कम 75 प्रतिशत पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाया जाएगा;

(ii) ऐसे पब्लिक इश्यू का 40 प्रतिशत फुटकर निवेशकों के लिए आवंटित किया जाएगा;

(छ) निजी नियोजन:- (i) बांड जारी करने में निजी नियोजन अपनाते समय प्रत्येक कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2008 के विनियमन 11 के अनुसार पुस्तक निर्माण दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिसमें कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन कूपन दर पर निविदा मांगी जाएगी और मूल्य निविदा पर आवंटन किया जाएगा;

(ii) बांड का भुगतान किया जाएगा और एक प्रीमियम पर जारी किया जाएगा किन्तु एक नियत कूपन के साथ ताकि लेखपत्र को एकल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) के तहत खरीदा-बेचा जा सके और लाभ को उद्धृत मूल्य पर निकाला जाएगा और तब सर्वश्रेष्ठ मूल्य (न्यूनतम लाभ) को आवंटन किया जाएगा;

(iii) ब्याज की उच्चतम दर दर पैराग्राफ (घ) में उल्लिखित दर के बराबर अथवा उससे कम होगी;

(iv) निविदा आमंत्रित करते समय व्यवस्थापकों को संख्या की कोई सीमा नहीं होगी जो इश्यू के लिए निविदा दे सकते हैं;

(v) प्रत्येक ट्रेन्च के लिए इश्यू का आकार पांच सौ करोड़ रुपये तक सीमित होगा;

(ज) बांड का पुनर्भुगतान:- (i) जारीकर्ता कंपनी उधार ली गई निधि एक बार पुनर्भुगतान के लिए देय होने की स्थिति में पुनर्भुगतान करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए वित्त मंत्रालय को एक वित्त-पोषण योजना प्रस्तुत करेगी;

(ii) इस वित्त-पोषण योजना को संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा विधिवत रूप से पुष्टीकरण के साथ इश्यू बंद होने के तीन माह के भीतर इंफ्रा-फाइनैस अनुभाग, अवसंरचना एवं निवेश प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा;

(इ) मर्चेट बैंकर्स का चयन:- मर्चेट बैंकर्स का चयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसमें पूर्व-योग्यता के लिए एकमात्र तकनीकी कसौटी पिछले पांच वर्षों में ऋण एवं इक्विटी दोनों के पब्लिक इश्यू के माध्यम से गतिशील कुल निधि होगी और पूर्व-योग्यता के बाद अंतिम चयन वित्तीय निविदा के आधार पर होगी;

(ज) उपरोक्त धारा 10 के अंतर्गत लाभ केवल तभी स्वीकार्य होगा यदि ऐसे बांड का धारक अपना या इसका नाम और धारणाधिकार को कंपनी में पंजीकृत करता/करती है।

सारणी

क्र.सं. (1)	कंपनी (2)	बांड की कुल राशि (3)
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	10,000 करोड़ रुपए
2	भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.	10,000 करोड़ रुपए
3	भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड	10,000 करोड़ रुपए
4	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	5,000 करोड़ रुपए
5	राष्ट्रीय आवास बैंक	5,000 करोड़ रुपए
6	विद्युत वित्त निगम	5,000 करोड़ रुपए
7	ग्रामीण विद्युत निगम	5,000 करोड़ रुपए
8	जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	2,000 करोड़ रुपए
9	ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	5,00 करोड़ रुपए
10	इन्नोर पोर्ट लिमिटेड	1,000 करोड़ रुपए

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,-

(i) योग्य सांस्थानिक क्रेता का वही अर्थ होगा जो उनको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रकटीकरण एवं निवेशक संरक्षा) दिशानिर्देश, 2000 में दिया गया है।

(ii) रिटेल व्यष्टिगत निवेशक का अर्थ उन व्यष्टिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार (कर्ता के माध्यम से) तथा प्रत्यावासन के साथ-साथ गैर प्रत्यावासन आधार पर अ-प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) से है जो प्रत्येक इश्यू में दस लाख रुपए तक के लिए आवेदन कर रहे हैं; और दस लाख रुपए से अधिक निवेश करने वाले व्यष्टिगत निवेशकों को उच्च निवल मूल्य व्यष्टियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) एनआरआई को जारी किए गए बांड समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 6 और 47 की उप-धारा (3) के खंड

(ख) के तहत जारी अधिसूचना संख्या फेमा 4/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 तथा अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

(iv) इस अधिसूचना के पैराग्राफ (घ) में उल्लिखित क्रेडिट रेटिंग का अर्थ उस क्रेडिट रेटिंग से होगा जो उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दिया जाएगा जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित होगा और जहां एक से अधिक एजेंसी द्वारा किसी कंपनी को भिन्न रूप से रेटिंग दी जाएगी तो वहां दोनों में से कम रेटिंग को ध्यान में रखा जाएगा।

[अधिसूचना सं. 46/2012/फा. सं. 178/60/2012-(आ.क.नि.-1)]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव (आ.क.नि.-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2012

S.O. 2685(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the entities mentioned in column (2) of the following Table, to issue, during the financial year 2012-13, tax-free, secured, redeemable, non-convertible bonds, aggregating to amounts mentioned in column (3) of the said table, subject to the conditions specified hereunder: -

- (a) **Eligibility.**— The following shall be eligible to subscribe to the bonds: -
 - (i) Retail Individual Investors (RII);
 - (ii) Qualified Institutional Buyers (QIBs);
 - (iii) Corporates;
 - (iv) High Net Worth Individuals (HNIs);
- (b) **Tenure of bonds.**— (i) In the case of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), the tenure of the bonds shall be for ten, fifteen or twenty years;
- (ii) in other cases, the tenure of the bonds shall be for ten or fifteen years ;
- (c) **Permanent Account Number.**— It shall be mandatory for the subscribers to furnish their Permanent Account Number to the issuer;
- (d) **Rate of interest .-** (i) There shall be a ceiling on the coupon rates based on the reference Government security (G-sec) rate;
- (ii) The reference G-sec rate would be the average of the base yield of G-sec for equivalent maturity reported by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) on a daily basis (working day) prevailing for two weeks ending on the Friday immediately preceding the filing of the final prospectus with the Exchange or Registrar of Companies (ROC) in case of public issue and the Issue opening date in case of private placement;

4242 GI/12-2

- (iii) The ceiling coupon rate for AA rated issuers shall be the reference G-sec rate less 50 basis points in case of Retail Individual Investors (RII); and reference G-sec rate less 100 basis points in case of other investor segments, like Qualified Institutional Buyers (QIBs), Corporate and High Net Worth Individuals (HNIs);
- (iv) In case the rating of the issuer entity is above AA, a reduction of 15 basis points shall be made in the ceiling rate, as compared to the ceiling rate for AA rated entities [as given in clause (iii)] ;
- (v) These ceiling rates shall apply for annual payment of interest and in case the schedule of interest payments is altered to semi-annual, the interest rates shall be reduced by 15 basis points;
- (vi) The higher rate of interest, applicable to retail investors, shall not be available in case the bonds are transferred, except in case of transfer to legal heir in the event of death of the original investor;
- (e) Issue expense and brokerage.-** (i) In the case of private placement, the total issue expense shall not exceed 0.2% of the issue size and in case of public issue it shall not exceed 0.5% of the issue size;
- (ii) The issue expense would include all expenses relating to the issue like brokerage, advertisement, printing, registration etc.;
- (iii) The brokerage, in cases of different categories, shall be limited to the following ceilings:-
- (I) QIB - 0.05%
 - (II) Corporates - 0.1%
 - (III) HNI - 0.15%
 - (IV) RII - 0.75%;
- (f) Public issue.-** (i) At least 75% of the aggregate amount of bonds issued by each entity shall be raised through public issue;.
- (ii) 40% of such public issue shall be earmarked for retail investors;
- (g) Private placement.-** (i) While adopting the private placement route to issue the bonds, each entity shall adopt the book building approach as per the Regulations 11 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations 2008, wherein bids shall be sought on the coupon rate subject to a ceiling specified by the entity and the allotment shall be made at the price bid;
- (ii) The bonds shall be paid for and issued at a premium but with a fixed coupon so that the instrument can be traded under a single International Securities Identification Number (ISIN) and the yield shall be worked based on the price quoted and then allotment shall be done for best price (lowest yield);
- (iii) The ceiling rate of the interest shall either be equal to or lower than the rate mentioned in paragraph (d);
- (iv) While calling for bids, there shall be no limit on the number of arrangers who can bid for the issue;
- (v) The issue size shall be limited to rupees five hundred crores for each tranche;
- (h) Repayment of bonds.-**(i) The issuer entity shall submit a financing plan to the Ministry of Finance to demonstrate its ability to repay the borrowed funds once the repayment becomes due;
- (ii) This financing plan shall be submitted to the Infra-Finance Section, Infrastructure and Investment Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, within three months of closure of the issue, duly supported by a resolution of the respective entity's Board of Directors;

- (i) **Selection of merchant bankers.**— Merchant bankers shall be selected through competitive bidding process wherein the only technical criteria for pre-qualification shall be the total funds mobilised through public issue of debt and equity together over the past five years and after pre-qualification, the final selection shall be based on financial bids;
- (j) The benefit under the aforesaid section 10 shall be admissible only if the holder of such bonds registers his, her or it's name and the holding with the entity.

Table

S.No. (1)	Entities (2)	Aggregate amount of bonds. (3)
1.	National Highways Authority of India	Rs. 10,000 crores
2.	Indian Railway Finance Corporation Limited	Rs. 10,000 crores
3.	India Infrastructure Finance Company Limited	Rs. 10,000 crores
4.	Housing and Urban Development Corporation Limited	Rs. 5,000 crores
5.	National Housing Bank	Rs. 5,000 crores
6.	Power Finance Corporation	Rs. 5,000 crores
7.	Rural Electrical Corporation	Rs. 5,000 crores
8.	Jawaharlal Nehru Port Trust	Rs. 2,000 crores
9.	Dredging Corporation of India Limited	Rs. 500 crores
10.	Ennore Port Limited	Rs. 1,000 crores

Explanation.— For the purposes of this notification,—

- (i) Qualified Institutional Buyers shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
- (ii) Retail Individual Investors means those individual investors, Hindu Undivided Family (through Karta), and Non Resident Indians (NRIs), on repatriation as well as non repatriation basis, applying for upto Rs. ten lakhs in each issue; and individual investors investing more than Rs. ten lakhs shall be classified as High Net Worth Individuals.
- (iii) The bonds issued to NRIs shall be subject to the provisions of Notification No. FEMA 4/2000-RB dated 3rd May, 2000 and Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, issued under clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended from time to time.
- (iv) The credit rating referred to in paragraph (d) of this notification shall mean the credit rating, as assigned by a credit rating agency which is approved by the Securities and Exchange Board of India as well as the Reserve Bank of India and where an entity has been rated differently, by more than one rating agency, the lower of the two ratings shall be considered.

[Notification No. 46/2012/F. No. 178/60/2012-(ITA. I)]

SURABHI SHARMA, Under Secy. (ITA. I)